

प्रधानमंत्री कार्यालय



इंदौर, मध्य प्रदेश में ठोस अपशिष्ट आधारित गोबर-धन संयंत्र के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री के भाषण का मूल पाठ

प्रविष्टि तिथि: 19 FEB 2022 4:11PM by PIB Delhi

नमस्कार !

मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्रीमान मंगू भाई पटेल जी, मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी श्री हरदीप सिंह पुरी जी, डॉ वीरेन्द्र कुमार जी, कौशल किशोर जी, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रिगण, सांसद-विधायकगण, इंदौर समेत मध्य प्रदेश के अनेक शहरों से जुड़े प्यारे भाइयों और बहनों, अन्य महानुभाव भी आज यहां मौजूद हैं।

हम जब छोटे थे, जब पढ़ते थे तो इंदौर का नाम आते ही सबसे पहले देवी अहिल्याबाई होल्कर, माहेश्वर, और उनके सेवाभाव का ध्यान जरूर आता था। समय के साथ इंदौर बदला, ज्यादा अच्छे के लिए बदला, लेकिन देवी अहिल्या जी की प्रेरणा को इंदौर ने कभी भी खोने नहीं दिया। देवी अहिल्या जी के साथ ही आज इंदौर का नाम आते ही मन में आता है- स्वच्छता। इंदौर का नाम आते ही मन में आता है- नागरिक कर्तव्य, जितने अच्छे इंदौर के लोग होते हैं, उतना ही अच्छा उन्होंने अपने शहर को बना दिया है। और आप सिर्फ सेब के ही शौकीन नहीं हैं, इंदौर के लोगों को अपने शहर की सेवा करनी भी आती है।

आज का दिन स्वच्छता के लिए इंदौर के अभियान को एक नई ताकत देने वाला है। इंदौर को आज गीले कचरे से बायो-सीएनजी बनाने का जो गोबरधन प्लांट मिला है, उसके लिए आप सभी को बहुत-बहुत बधाई। मैं शिवराज जी और उनकी टीम की विशेष प्रशंसा करूंगा जिसने इस कार्य को इतने कम समय में संभव बनाया है। मैं आज सुमित्रा ताई का भी आभार व्यक्त करूंगा जिन्होंने सांसद के तौर पर इंदौर की पहचान को नई ऊंचाई पर पहुंचाया। इंदौर के वर्तमान सांसद मेरे साथी भाई शंकर लालवानी जी भी उनके नक्शे-कदम पर उन्होंने जिस राह को तय किया उस राह पर इंदौर को आगे बढ़ाने के लिए उसे और बेहतर बनाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं।

और साथियों,

आज जब मैं इंदौर की इतनी प्रशंसा कर रहा हूँ, तो अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का भी जिक्र करूंगा। मुझे खुशी है कि काशी विश्वनाथ धाम में देवी अहिल्याबाई होल्कर जी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा रखी गई है। इंदौर के लोग जब बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जाएंगे, तो उन्हें वहां देवी अहिल्याबाई जी की मूर्ति भी दर्शन करने के लिए मिलेगी। आपको अपने शहर पर और गर्व होगा।

साथियों,

अपने शहरों को प्रदूषण मुक्त रखने, और गीले कचरे के निस्तारण के लिए आज का ये प्रयास बहुत अहम है। शहर में घरों से निकला गीला कचरा हो, गांव में पशुओं-खेतों से मिला कचरा हो, ये सब एक तरह से गोबरधन ही है। शहर के कचरे और पशुधन से गोबरधन, फिर गोबरधन से स्वच्छ ईंधन, फिर स्वच्छ ईंधन से ऊर्जाधन, ये श्रृंखला जीवनधन का निर्माण करती है। इस श्रृंखला की हर कड़ी कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई है, उसके प्रत्यक्ष प्रमाण के तौर पर इंदौर का ये गोबरधन प्लांट अब दूसरे शहरों को भी प्रेरणा देगा।

मुझे खुशी है कि आने वाले दो वर्षों में देश के 75 बड़े नगर निकायों में इस प्रकार के गोबरधन बायो सीएनजी प्लांट बनाने पर काम किया जा रहा है। ये अभियान भारत के शहरों को स्वच्छ बनाने, प्रदूषण रहित बनाने, क्लीन एनर्जी की दिशा में बहुत मदद करेगा। और अब तो शहरों में ही नहीं, बल्कि देश के गांवों में भी हजारों की संख्या में गोबरधन बायोगैस प्लांट लगाए जा रहे हैं। इनसे हमारे पशुपालकों को गोबर से भी अतिरिक्त आय मिलनी शुरू हुई है। हमारे गांव-देहात में किसानों को बेसहारा जानवरों से जो दिक्कत होती है, वो भी इस तरह के गोबरधन प्लांट्स से कम होगी। ये सारे प्रयास, भारत के क्लाइमेट कमिटमेंट को भी पूरा करने में मदद करेंगे।

साथियों,

गोबरधन योजना यानि कचरे से कंचन बनाने के हमारे अभियान का जो असर हो रहा है, उसकी जानकारी जितनी ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले, वो उतना ही अच्छा है। गोबरधन बायो-सीएनजी प्लांट से इंदौर को प्रतिदिन 17 से 18 हजार किलो बायो-सीएनजी तो मिलेगी ही, इसके अलावा 100 टन जैविक खाद भी यहां से रोजाना निकलेगी। सीएनजी के कारण, प्रदूषण कम होगा और इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने में सुविधा बढ़ेगी। इसी प्रकार से, यहां जो जैविक खाद बनेगी, उससे हमारी धरती मां को भी नया जीवन मिलेगा, हमारी धरती का कायाकल्प होगा।

एक अनुमान है कि इस प्लांट में जो सीएनजी बनेगी उससे इंदौर शहर में हर रोज करीब-करीब 400 बसें चलाई जा सकेंगीं। इस प्लांट से सैकड़ों युवाओं को किसी ना किसी रूप में रोजगार भी मिलने वाला है, यानि ये ग्रीन जॉब्स को बढ़ाने में भी मददगार होगा।

भाइयों और बहनों,

किसी भी चुनौती से निपटने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये कि उस चुनौती का तात्कालिक समाधान कर दिया जाए। दूसरा ये होता है कि उस चुनौती से ऐसे निपटा जाए कि सभी को स्थाई समाधान मिले। बीते सात वर्षों में हमारी सरकार ने जो योजनाएं बनाई हैं, वो योजनायें स्थाई समाधान देने वाली होती हैं, एक साथ कई लक्ष्यों को साधने वाली होती हैं।

स्वच्छ भारत अभियान को ही लीजिए। इससे स्वच्छता के साथ-साथ बहनों की गरिमा, बीमारियों से बचाव, गांव-शहरों को सुंदर बनाने, और रोजगार के अवसर तैयार करने जैसे अनेक काम एक साथ हुए हैं। अब हमारा फोकस घर से, गली से निकले कचरे के निस्तारण का है, शहरों को कूड़े के पहाड़ों से मुक्त करने का है। इनमें भी इंदौर एक बेहतरीन मॉडल बनकर उभरा है। आप भी जानते हैं कि ये नया प्लांट जहां लगा है, वहां पास ही देवगुडरिया में कूड़े का पहाड़ होता था। हर इंदौरवासी को इससे दिक्कत थी। लेकिन अब इंदौर नगर निगम ने 100 एकड़ की इस डंप साइट को ग्रीन ज़ोन में बदल दिया है।

साथियों,

आज देशभर के शहरों में लाखों टन कूड़ा, दशकों से ऐसी ही हजारों एकड़ ज़मीन घेरे हुए है। ये शहरों के लिए वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण से होने वाली बीमारियों की भी बड़ी वजह है। इसलिए स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण में इस समस्या से निपटने के लिए काम किया जा रहा है। लक्ष्य ये है कि आने वाले 2-3 वर्षों में कूड़े के इन पहाड़ों से हमारे शहरों को मुक्ति मिल सके, उन्हें ग्रीन ज़ोन्स में बदला जा सके।

इसके लिए राज्य सरकारों को हर संभव मदद दी जा रही है। ये भी अच्छी बात है कि साल 2014 की तुलना में अब देश में शहरी कूड़े के निस्तारण की क्षमता 4 गुना तक बढ़ चुकी है। देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति दिलाने के लिए 1600 से अधिक निकायों में Material Recovery Facility भी तैयार की जा रही है। हमारा प्रयास है कि अगले कुछ वर्षों में देश के हर शहर में इस तरह की व्यवस्था का निर्माण हो। इस तरह की आधुनिक व्यवस्थाएं भारत के शहरों में सर्कुलर इकॉनॉमी को भी एक नई शक्ति दे रही हैं।

साथियों,

स्वच्छ होते शहर से एक और नई संभावना जन्म लेती है। ये नई संभावना है पर्यटन की। हमारे देश में ऐसा कोई शहर नहीं जहां ऐतिहासिक स्थल ना हों, पवित्र स्थल ना हों। कमी जो रही है, वो है स्वच्छता की। जब शहर स्वच्छ होंगे तो दूसरी जगहों से लोगों को भी वहां आने का मन करेगा, लोग ज्यादा आएंगे। अब जैसे कितने ही लोग तो केवल ये देखने इंदौर आते हैं कि देखें,

सफाई के लिए आपके यहां काम हुआ है, जरा जा करके देखें तो सही। जहां स्वच्छता होती है, पर्यटन होता है, वहां पूरी एक नई अर्थव्यवस्था चल पड़ती है।

साथियों,

हाल ही में इंदौर ने Water Plus होने की उपलब्धि भी हासिल की है। ये भी अन्य शहरों को दिशा दिखाने वाला काम हुआ है। जब किसी शहर के जलस्रोत साफ होते हैं, नाले का गंदा पानी उनमें नहीं गिरता, तो एक अलग ही जीवंत ऊर्जा उस शहर में आ जाती है। सरकार का प्रयास है कि भारत के ज्यादा से ज्यादा शहर Water Plus बनें। इसके लिए स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण पर जोर दिया जा रहा है। एक लाख से कम आबादी वाले जो नगर निकाय हैं, वहां गंदे पानी के ट्रीटमेंट की सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं।

भाइयों और बहनों,

समस्याओं को पहचानकर अगर ईमानदार प्रयास किए जाएं तो बदलाव संभव होता है। हमारे पास तेल के कुएं नहीं हैं, पेट्रोलियम के लिए हमें बाहर depended रहना पड़ता है, लेकिन हमारे पास बायोफ्यूल के, इथेनॉल बनाने के संसाधन बरसों से मौजूद रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी भी काफी पहले आ चुकी थी। ये हमारी ही सरकार है जिसने इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर बहुत ज्यादा जोर दिया। 7-8 साल पहले भारत में इथेनॉल ब्लेंडिंग मुश्किल से 1 परसेंट, डेढ़ परसेंट, 2 परसेंट, इससे आगे नहीं बढ़ रहा था। आज पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग का प्रतिशत, 8 परसेंट के आस-पास पहुंच रहा है। बीते सात वर्षों में ब्लेंडिंग के लिए इथेनॉल की सप्लाई को भी बहुत ज्यादा बढ़ाया गया है।

साल 2014 से पहले देश में करीब 40 करोड़ लीटर इथेनॉल, ब्लेंडिंग के लिए सप्लाई होता था। आज भारत में 300 करोड़ लीटर से ज्यादा इथेनॉल, ब्लेंडिंग के लिए सप्लाई हो रहा है। कहां 40 करोड़ लीटर और कहां 300 करोड़ लीटर! इससे हमारी चीनी मिलों की सेहत सुधरी है और गन्ना किसानों को भी बहुत ज्यादा मदद मिली है।

साथियों

एक और विषय है पराली का। पराली से हमारे किसान भी परेशान रहे हैं और शहरों में रहने वाले लोग भी। हमने इस बजट में पराली से जुड़ा एक अहम फैसला किया है। ये तय किया गया है कि कोयले से चलने वाले बिजली कारखानों में पराली का भी उपयोग किया जाएगा। इससे किसान की परेशानी तो दूर होगी ही, खेती के कचरे से किसान को अतिरिक्त आय भी मिलेगी।

ऐसे ही हमने ये भी देखा है कि पहले सौर ऊर्जा- सोलर पावर को लेकर कितनी उदासीनता थी। 2014 के बाद से हमारी सरकार ने पूरे देश में सोलर पावर का उत्पादन बढ़ाने के लिए अभियान चलाया हुआ है। इसी का परिणाम है कि आज भारत ने सोलर पावर से बिजली बनाने के मामले में दुनिया के टॉप-5 देशों में अपनी जगह बना ली है। इसी सोलर पावर की शक्ति से हमारी सरकार किसानों को अन्नदाता के साथ ही ऊर्जादाता भी बना रही है, अन्नदाता ऊर्जादाता बने। देश भर के किसानों को लाखों सोलर पंप भी दिए जा रहे हैं।

भाइयों और बहनों,

आज भारत जो कुछ भी हासिल कर रहा है, उसमें टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के साथ ही भारतीयों के परिश्रम का भी बहुत बड़ा हाथ है। इसी वजह से आज भारत, ग्रीन और क्लीन फ्यूचर को लेकर बड़े लक्ष्य रख पा रहा है। हमारे युवाओं, हमारी बहनों, हमारे लाखों-लाख सफाई कर्मचारियों पर अटूट भरोसा करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। भारत के युवा नई टेक्नोलॉजी, नए इनोवेशन के साथ-साथ जन-जागरण में भी बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं।

जैसे मुझे बताया गया है कि इंदौर की जागरूक बहनों ने कूड़े के प्रबंधन को एक अलग मुकाम पर पहुंचा दिया है। इंदौर के लोग कूड़े को 6 हिस्सों में अलग-अलग करते हैं, जिससे कूड़े की Processing और Recycling ठीक से हो सकती है। किसी भी शहर के लोगों की यही भावना, यही प्रयास, स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने में मददगार साबित होते हैं। स्वच्छता के साथ-साथ रिसाइक्लिंग के संस्कारों को भी सशक्त करना, अपने आप में देश की बड़ी सेवा है। यही तो LIFE यानि life style for environment का दर्शन है, जीवन जीने का तरीका है।

साथियों,

आज के इस कार्यक्रम में, मैं इंदौर के साथ ही, देशभर के लाखों सफाई कर्मियों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। सदी हो, गर्मी हो, आप सुबह-सुबह निकल पड़ते हैं अपने शहर को स्वच्छ बनाने के लिए। कोरोना के इस मुश्किल समय में भी आपने जो सेवाभाव दिखाया है, उसने कितने ही लोगों का जीवन बचाने में मदद की है। ये देश, अपने हर सफाईकर्मी भाई-बहन का अत्यंत ऋणी है। अपने शहरों को स्वच्छ रखकर, गंदगी ना फैलाकर, नियमों का पालन करके, हम उनकी मदद कर सकते हैं।

मुझे याद है, प्रयागराज में कुंभ के दौरान, आपने देखा होगा दुनिया में पहली बार भारत के कुंभ मेले की एक नई पहचान बनी। पहले तो भारत के कुंभ मेले की पहचान हमारे साधु-महात्मा, उन्हीं के आस-पास बातें चलती थीं। लेकिन पहली बार उत्तर प्रदेश में योगीजी के नेतृत्व में प्रयागराज में जो कुंभ हुआ, उसकी पहचान स्वच्छ कुंभ के रूप में हुई। पूरे विश्व में चर्चा हुई। दुनिया के अखबारों ने कुछ न कुछ उसके लिए लिखा। ये मेरे मन पर इसका बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव है। तो मैं जब कुंभ के मेले में पवित्र स्नान के लिए गया था तो स्नान कर के आने के बाद मेरे मन में इन सफाई कर्मियों के लिए इतना अहोभाव उठा था कि मैंने इन सफाई कर्मियों के पांव धोए थे। उनका सम्मान किया था। उनसे मैंने आशीर्वाद लिए थे।

आज मैं दिल्ली से, इंदौर के अपने हर सफाईकर्मी भाई-बहन को आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। उनका नमन करता हूं। इस कोरोना काल में आप लोगों ने इस सफाई के अभियान को जारी न रखा होता तो न जाने हम कितनी नई-नई मुसीबतों को झेलते। आपने इस देश के सामान्य मानवी को बचाने में, डॉक्टर तक न जाना पड़े, इसके लिए जो चिंता की है ना, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं।

भाइयो, बहनों

इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार फिर सभी इंदौरवासियों को, खास करके इंदौर की मेरी माताओं-बहनों को, क्योंकि उन्होंने ये काम में जो initiative लिया है, कूड़ा-कचरा बिल्कुल बाहर फेंकना नहीं, उसका segregation करना, ये मेरी माताएं-बहनें, अनेक-अनेक अभिनंदन की अधिकारी हैं और मेरी बाल-सेना जो घर में किसी को कूड़ा-कचरा फेंकने नहीं देती है। पूरे हिंदुस्तान में स्वच्छता अभियान को सफल करने में मेरी बाल सेना ने बहुत मेरी मदद की है। तीन-तीन, चार-चार साल के बच्चे अपने दादा को कहते हैं कूड़ा-कचरा यहां मत फेंको। चॉकलेट खाई है, ये यहां नहीं फेंकना है, कागज यहां नहीं फेंकना है। ये जो बाल-सेना ने काम किया है, ये भी हमारे भावी भारत की नींव को मजबूत करने वाली बात है। मैं इन सबको आज हृदय से अभिनंदन करते-करते आप सबको बायो-सीएनजी प्लांट के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूं!

बहुत-बहुत धन्यवाद! नमस्कार!

DS/ST/NS

(रिलीज आईडी: 1799615) आगंतुक पटल : 502

इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English , Urdu , Marathi , Bengali , Assamese , Manipuri , Punjabi , Gujarati , Odia , Tamil , Telugu , Kannada , Malayalam

प्रधानमंत्री कार्यालय



केन्द्रीय बजट के बाद 'सतत विकास के लिए ऊर्जा' विषय पर वेबिनार में प्रधानमंत्री के संबोधन का मूल पाठ

प्रविष्टि तिथि: 04 MAR 2022 1:37PM by PIB Delhi

नमस्कार!

'Energy for Sustainable Growth', ये हमारी पुरातन परंपराओं से भी प्रेरित है और भविष्य की आवश्यकताओं-आकांक्षाओं की पूर्ति का मार्ग भी है। भारत का clear vision है कि Sustainable Growth, Sustainable Energy Sources से ही संभव है। ग्लासगो में हमने 2070 तक नेट-जीरो के स्तर तक पहुंचने का वादा किया है।

मैंने Cop-26 में Sustainable Lifestyle को बढ़ावा देने के लिए भी LIFE मिशन की बात कही थी, यानी Lifestyle For Environment का विजन सामने रखा था। हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे ग्लोबल collaboration का भी नेतृत्व कर रहे हैं। Non-Fossil Energy Capacity में हमारा टारगेट अपने लिए 500 गीगावाट है। 2030 तक अपनी Installed Energy Capacity का 50 percent हमें Non-Fossil Energy से हासिल करना है। भारत ने अपने लिए जो भी टारगेट सेट किए हैं, उसे मैं चैलेंज की तरह नहीं बल्कि Opportunities की तरह देखता हूं। इसी vision पर भारत बीते वर्षों से चल रहा है और इस बजट में इनको policy level पर और आगे बढ़ाया गया है।

Friends,

इस बजट में सोलर एनर्जी की दिशा में High-Efficiency Solar Module Manufacturing के लिए साढ़े 19 हजार करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। इससे Solar Modules और इससे जुड़े प्रॉडक्ट्स की Manufacturing और R&D में भारत को ग्लोबल हब बनाने में मदद मिलेगी।

साथियों,

हमने नेशनल हाइड्रोजन मिशन की भी घोषणा की है। भारत के पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध Renewable Energy Power के रूप में एक Inherent Advantage है। इससे भारत विश्व में Green Hydrogen का हब बन सकता है। Hydrogen Eco-System फर्टिलाइजर, रिफाइनरीज और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से Inter-Connected है। ये एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें Private Sector द्वारा Innovations को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ताकि भारत की पूरी क्षमता का उपयोग किया जा सके।

साथियों,

Renewable Energy के साथ एक बड़ा Challenge Energy Storage को लेकर भी है। इसके लिए भी Solutions तलाशने के लिए बजट में Storage Capacity में Growth को बनाये रखने के लिए बड़ी priority दी गयी है। इस वर्ष के बजट में Battery Swapping Policy और Inter Operability Standards के बारे में भी Provision किये गए हैं। इनसे भारत में Electric Vehicle के इस्तेमाल में आने वाली दिक्कतें कम होंगी। Plug-In चार्जिंग में ज्यादा समय और ज्यादा कीमत लगती है। क्योंकि Electric Vehicle की कीमत में 40-50 परसेंट बैटरी की कीमत होती है, इसलिए swapping से Electric Vehicle की Upfront Cost कम हो जाएगी। ऐसे ही चाहे मोबाइल की बैटरी हो या फिर सोलर पावर स्टोरेज, इस क्षेत्र में भी बहुत सी संभावनाएं हैं। इन पर भी मैं समझता हूं हम सब मिल कर काम कर सकते हैं।

साथियों,

Sustainability के लिए Energy Production के साथ ही Energy Saving भी उतनी ही आवश्यक है। हमारे देश में और अधिक Energy Efficient A/C कैसे बनें, और अधिक Energy Efficient हीटर, गीजर, Oven कैसे बनें, इस बारे में बहुत कुछ करने की आवश्यकता मुझे लगती है। जहां भी बिजली की खपत ज्यादा है, वहां Energy Efficient Products का निर्माण हम सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए।

मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जब 2014 में हमारी सरकार आई, तो देश में LED बल्ब की कीमत 300-400 रुपये हुआ करती थी। हमारी सरकार ने LED बल्ब का प्रोडक्शन बढ़ाया और प्रॉडक्शन बढ़ने के बाद स्वाभाविक था कि इसकी कीमत 70-80 रुपये तक नीचे आई। उजाला योजना के तहत हमने देश में करीब-करीब 37 करोड़ LED बल्ब बांटे। इससे लगभग Forty Eight Thousand Million Kilo Watt Hour बिजली बची है। हमारे गरीब और मध्यम वर्ग का सालाना करीब 20 हजार करोड़ रुपये का बिजली बिल भी बचा है। और प्रतिवर्ष करीब 4 करोड़ टन कार्बन एमिशन कम हुआ है। हमने परंपरागत स्ट्रीट लाइट्स को भी सवा करोड़ स्मार्ट LED बल्बों से बदला है, उससे भी हमारे जो स्थानीय निकाय हैं, नगर पालिका, महानगर पालिका, जहां पंचायतों में इस प्रकार की स्ट्रीट लाइट हैं, अब तक जितना काम हुआ है उसमें साल का 6 हजार करोड़ रुपये के बिजली के बिल में बचत हुई है, नगर पालिकाओं को। इससे भी बिजली बची है, और करीब 50 लाख टन कार्बन एमिशन भी कम हुआ है। आप कल्पना कर सकते हैं कि इस एक योजना ने पर्यावरण की कितनी बड़ी रक्षा की है।

साथियों,

Coal Gasification कोयले के एक विकल्प के रूप में हम सोच सकते हैं। इस साल के बजट में Coal Gasification के लिए 4 Pilot projects रखे गए हैं जिसमें technical और Financial Viability प्राप्त करने को बल मिलेगा। और इसमें इनोवेशन्स की जरूरत है। और मैं चाहता हूं कि इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग Coal Gasification को भारत की आवश्यकता के अनुसार इसमें इनोवेशन के साथ कैसे आ सकते हैं, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए।

ऐसे ही आप देखते हैं एक बड़े मिशन मोड में सरकार Ethanol Blending को भी निरंतर बढ़ावा दे रही है। इस बजट में Unblended Fuel पर Extra Differential Excise Duty का Provision किया गया है। हमें अपनी Sugar Mills और Distilleries को और अधिक आधुनिक बनाने की जरूरत है। इसमें भी technology up gradation आवश्यक है। इसके लिए हमें ऐसे Distilling Processes पर काम करना होगा जिनसे Potash और Compressed Bio-Gas जैसे By-Products भी हमें अतिरिक्त प्राप्त हों।

कुछ सप्ताह पहले मैंने वाराणसी में और अभी कुछ दिन पहले इंदौर में भी गोबरधन प्लांट का उद्घाटन किया है। क्या अगले 2 साल में देश में 500 या 1000 ऐसे गोबरधन प्लांट प्राइवेट सेक्टर द्वारा स्थापित किए जा सकते हैं। इंडस्ट्री को इसी तरह इन Possibilities को Utilize करने के लिए Innovative Investments करने की जरूरत मुझे लगती है।

Friends,

हमारी Energy Demand लगातार बढ़ने वाली है। इसलिए, Renewable Energy की ओर Transition भारत के लिए और भी अहम है। एक अनुमान है कि भारत में 24-25 करोड़ घर हैं। हम Clean-Cooking को कैसे कैसे आगे बढ़ाएँ। मैं समझता हूं, हमारे स्टार्टअप के लोग भी इस काम को बड़ी आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं। आपके लिए Solar चूल्हे के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा मार्केट है, जो Clean-Cooking Movement के लिए जरूरी है। आपने देखा होगा, गुजरात में एक सफल प्रयोग हुआ था, पानी की जो कैनॉल्स हैं, नहर हैं, उस पर हमने सोलर पैनल लगाई, जमीन का खर्चा बच गया, पानी की बचत हो गई, बिजली भी उत्पादन हुई, यानी Multiple Benefit हुआ। ऐसा ही प्रयोग अब देश में अन्य जगहों पर नदियों और झीलों में भी किया जा रहा है। हमें इसको भी और ज्यादा बढ़ाना चाहिए।

एक और काम, घरों में किया जा सकता है। घर में जहां बाग-बगीचा होता है, या फिर बालकनी होती है, क्या हम जो Gardening Concept है, उसमें एक सोलर ट्री। हर परिवार का अपना एक सोलर ट्री हो वैसा एक नया Concept डेवलप कर सकते हैं, जो घर की 10-15 परसेंट, 20 परसेंट बिजली में वो सोलर ट्री मदद कर सकते हैं। और घर की पहचान भी बन जाएगी कि भई ये सोलर ट्री वाला घर है, यानी एनवायरमेंट के प्रति जागरूक नागरिकों का घर है। एक समाज में विशेष Credible Society के रूप में हम डेवलप हो सकते हैं। और इसको बड़ा Easily और Beautiful भी बनाया जा सकता है। तो सोलर ट्री के कंसेप्ट को मैं तो हमारी जो कंस्ट्रक्शन की दुनिया के लोग हैं, बिल्डर लोग हैं और आर्किटेक्चर हैं, उनसे भी मैं कहूंगा कि घर के कंस्ट्रक्शन में एक नया तरीका हम जोड़ सकते हैं क्या।

हमारे देश में माइक्रो हाइड्रल प्रॉडक्ट्स भी बहुतायत में मिलते हैं। उत्तराखंड-हिमाचल में हम देखते हैं घराट नाम की पनचक्की बहुत होती है। माइक्रो हाइड्रल प्रॉडक्ट्स पर और रिसर्च करके हम इनके इस्तेमाल से बिजली उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पर भी काम किया जाना चाहिए। दुनिया में हर प्रकार की प्राकृतिक संपदा की, Natural Resources की Shortage होती जा रही है। ऐसे में सर्कुलर इकोनॉमी समय की मांग है और इसको जीवन का अनिवार्य हिस्सा बनाना ही पड़ेगा। हमारे लिए हर क्षेत्र में Innovation बहुत जरूरी है, नए Products जरूरी हैं, और मैं देश के प्राइवेट सेक्टर को भरोसा देता हूं कि सरकार आपके प्रयासों में आपके साथ खड़ी है।

हम एकजुट प्रयासों से इस दिशा में न केवल अपने लक्ष्य हासिल करेंगे, बल्कि पूरी मानवता का भी पथप्रदर्शन करेंगे।

साथियों,

मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आमतौर पर बजट बनने से पहले बहुत चर्चाएं होती हैं। हमारे टीवी चैनल्स वगैरह सब उसमें काफी बिजी होते हैं, एक अच्छा मंथन होता है और उसका बजट को भी थोड़ा लाभ होता है। बजट बनाने में काफी अच्छे-अच्छे आइडियाज मिलते हैं। लेकिन अब हमने फोकस किया है, चलो बजट बन गया, अब बजट में कोई परिवर्तन होना नहीं है। पार्लियामेंट की वो अमानत होती है, पार्लियामेंट तय करती है। हमारे पास दो महीने का समय होता है। बजट implement करने के लिए एक अप्रैल से। इस दो महीने का उपयोग हम implementation के रोडमैप पर बल कैसे दें और योजना अच्छे से अच्छे ढंग से कैसे हम लागू करें। बजट का अच्छे से अच्छे ढंग से उपयोग कैसे करें।

सरकार के सोचने का तरीका और फील्ड में काम करने वाले व्यापार जगत के तरीके में काफी अंतर होता है। इस सेमिनार से उस अंतर को पाटने को प्रयास हो। जो स्टैक होल्डर्स हैं उनकी thinking process और सरकार में जो निर्णय करते हैं उनकी thinking process, उसमें अंतरविरोध नहीं होना चाहिए। उसमें फासला भी नहीं होना चाहिए। अगर ये होता है तो चीजें बहुत जल्दी लागू होती हैं। कभी-कभार एकाध वाक्य ऐसा आ जाता है फाइल में कि फिर उसको correct करने में 6-6, 8-8 महीने लग जाते हैं। बजट का टाइम ही पूरा हो जाता है।

हम इन गलतियों से बचना चाहते हैं। और इसलिए ये जो हम वेबिनार कर रहे हैं, उसमें हम सरकार की तरफ से आपको ज्ञान परोसने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम बजट क्या है वो समझाने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम से ज्यादा समझ आप समझ चुके हैं। हम आपको सुनने के लिए वेबिनार करते हैं और सुनने में भी बजट के लिए सुझाव नहीं, जो बजट बन चुका है उसको इस क्षेत्र में हम लागू कैसे करेंगे, जल्दी से जल्दी लागू कैसे करेंगे, ज्यादा से ज्यादा outcome के साथ हम कैसे आगे बढ़ेंगे। हमारी ऐसी कोई व्यूह रचना न बन जाए जो बिना कारण समय खराब करे दे और इसलिए तेज गति लाने के लिए मैं चाहता हूं कि आप लोग concrete practical example और suggestions के साथ इस वेबिनार को सफल बनाएं।

मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

DS/ST/NS

(रिलीज आईडी: 1802893) आगंतुक पटल : 383

इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: Telugu , Urdu , Marathi , Punjabi , Odia , Manipuri , Kannada , English , Assamese , Bengali , Gujarati , Tamil , Malayalam

प्रधानमंत्री कार्यालय



विद्युत क्षेत्र की पुनर्ोत्थान वितरण क्षेत्र योजना के शुभारंभ के अवसर पर प्रधानमंत्री के संबोधन का मूल पाठ

प्रविष्टि तिथि: 30 JUL 2022 3:43PM by PIB Delhi

केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगीगण, विभिन्न राज्यों के आदरणीय मुख्यमंत्री साथी, पावर और एनर्जी सेक्टर से जुड़े अन्य सभी महानुभाव, देवियों और सज्जनों,

आज का ये कार्यक्रम, 21वीं सदी के नए भारत के नए लक्ष्यों और नई सफलताओं का प्रतीक है। आजादी के इस अमृतकाल में भारत ने, अगले 25 वर्षों के विजन पर काम करना शुरू कर दिया है। अगले 25 वर्षों में भारत की प्रगति को गति देने में एनर्जी सेक्टर, पावर सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका है। एनर्जी सेक्टर की मजबूती Ease of Doing Business के लिए भी जरूरी है और Ease of Living के लिए भी उतनी ही अहम है। हम सभी ने देखा है कि अभी मेरी जिन लाभार्थी साथियों से बात हुई, उनके जीवन में बिजली कितना बड़ा बदलाव लाई है।

साथियों,

आज हजारों करोड़ रुपए के जिन प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग और लोकार्पण हुआ है, वो भारत की energy security और green future की दिशा में अहम कदम हैं। ये प्रोजेक्ट renewable energy के हमारे लक्ष्यों, ग्रीन टेक्नॉलॉजी के हमारे कमिटमेंट और green mobility की हमारी आकांक्षाओं को बल देने वाले हैं। इन प्रोजेक्ट्स से देश में बड़ी संख्या में Green Jobs का भी निर्माण होगा। ये प्रोजेक्ट भले ही, तेलंगाना, केरला, राजस्थान, गुजरात और लद्दाख से जुड़े हैं, लेकिन इनका लाभ पूरे देश को होने वाला है।

साथियों,

हाइड्रोजन गैस से देश की गाड़ियों से लेकर देश की रसोई तक चलें, इसको लेकर बीते वर्षों में बहुत चर्चा हुई है। आज इसके लिए भारत ने एक बड़ा कदम उठाया है। लद्दाख और गुजरात में ग्रीन हाइड्रोजन, उसके दो बड़े प्रोजेक्ट्स पर आज से काम शुरू हो रहा है। लद्दाख में लग रहा प्लांट देश में गाड़ियों के लिए ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। ये देश का पहला प्रोजेक्ट होगा जो ग्रीन हाइड्रोजन आधारित ट्रांसपोर्ट के कमर्शियल इस्तेमाल को संभव बनाएगा। यानी लद्दाख देश का पहला स्थान होगा जहां बहुत ही जल्द Fuel cell electric vehicle चलने शुरू होंगे। ये लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल क्षेत्र बनाने में भी मदद करेगा।

साथियों,

देश में पहली बार, गुजरात में Piped Natural Gas में Green Hydrogen की ब्लेंडिंग का भी प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। अभी तक हमने पेट्रोल और हवाई ईंधन में इथेनॉल की ब्लेंडिंग की है, अब हम Piped Natural Gas में ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंड करने की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे नैचुरल गैस के लिए विदेशी निर्भरता में कमी आएगी और जो पैसा विदेश जाता है, वो भी देश के ही काम आएगा।

साथियों,

8 साल पहले देश के पावर सेक्टर की क्या स्थिति थी, ये इस कार्यक्रम में बैठे सभी दिग्गज साथियों को पता है। हमारे देश में ग्रिड को लेकर दिक्कत थी, ग्रिड फेल हुआ करते थे, बिजली का उत्पादन घट रहा था, कटौती बढ़ रही थी, डिस्ट्रिब्यूशन डांवाडोल था। ऐसी स्थिति में 8 साल पहले हमने देश के पावर सेक्टर के हर अंग को ट्रांसफॉर्म करने का बीड़ा उठाया।

बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए चार अलग-अलग दिशाओं में एक साथ काम किया गया-Generation, Transmission, Distribution और सबसे महत्वपूर्ण Connection. आप भी जानते हैं कि ये सभी आपस में एक दूसरे से किस तरह जुड़े हुए हैं। अगर Generation नहीं होगा, Transmission-Distribution system मजबूत नहीं होगा, तो Connection देकर भी कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा बिजली पैदा करने के लिए, पूरे देश में बिजली के प्रभावी वितरण के लिए, ट्रांसमिशन से जुड़े पुराने नेटवर्क के आधुनिकीकरण के लिए, देश के करोड़ों घरों तक बिजली कनेक्शन पहुंचाने के लिए हमने पूरी शक्ति लगा दी।

इन्हीं सब प्रयासों का नतीजा ये है कि आज सिर्फ देश के हर घर तक बिजली ही नहीं पहुंच रही, बल्कि ज्यादा से ज्यादा घंटे बिजली मिलने भी लगी है। पिछले 8 वर्षों में देश में लगभग 1 लाख 70 हजार मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता जोड़ी गई है। वन नेशन वन पावर ग्रिड आज देश की ताकत बन चुका है। पूरे देश को जोड़ने के लिए लगभग 1 लाख 70 हजार सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन्स बिछाई गई हैं। सौभाग्य योजना के तहत लगभग 3 करोड़ बिजली कनेक्शन देकर हम सैचुरेशन के लक्ष्य तक भी पहुंच रहे हैं।

साथियों,

हमारा पावर सेक्टर efficient हो, effective हो और बिजली सामान्य जन की पहुंच में हो, इसके लिए बीते वर्षों में निरंतर ज़रूरी रिफॉर्म किए गए हैं। आज जो नई पावर रिफॉर्म योजना शुरू हुई है, वो भी इसी दिशा में उठाया गया एक और कदम है। इसके तहत बिजली का नुकसान कम करने के लिए smart metering जैसी व्यवस्थाएं भी की जाएंगी, जिससे efficiency बढ़ेगी। बिजली का जो उपभोग होता है, उसकी शिकायतें खत्म हो जाएंगी। देशभर की DISCOMS को ज़रूरी आर्थिक मदद भी दी जाएगी, ताकि ये आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर सकें और आर्थिक रूप से खुद को सशक्त करने के लिए आवश्यक रिफॉर्म भी कर सकें। इसमें DISCOMS की ताकत बढ़ेगी और जनता को पर्याप्त बिजली मिल पाएगी और हमारा पावर सेक्टर और मजबूत होगा।

साथियों,

अपनी एनर्जी सेक्योरिटी को मजबूत करने के लिए आज भारत जिस तरह रीन्युएबल एनर्जी पर बल दे रहा है, वो अभूतपूर्व है। हमने आज़ादी के 75 साल पूरे होने तक 175 गीगावाट रीन्युएबल एनर्जी, ये कैपेसिटी तैयार करने का संकल्प लिया था। आज हम इस लक्ष्य के करीब पहुंच चुके हैं। अभी तक non fossil sources से लगभग 170 गीगावाट कैपेसिटी install भी हो चुकी है। आज installed solar capacity के मामले में भारत, दुनिया के टॉप 4 या 5 देशों में है। दुनिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट्स में आज अनेक ऐसे हैं जो हिन्दुस्तान में हैं, भारत में हैं। इसी कड़ी में आज दो और बड़े सोलर प्लांट्स देश को मिले हैं। तेलंगाना और केरला में बने ये प्लांट्स देश के पहले और दूसरे नंबर के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स हैं। इनसे Green Energy तो मिलेगी ही, सूर्य की गर्मी से जो पानी भाप बनकर उड़ जाता था, वो भी नहीं होगा। राजस्थान में एक हजार मेगावाट क्षमता वाले सिंगल लोकेशन सोलर पावर प्लांट के निर्माण का भी आज से काम शुरू हो चुका है। मुझे विश्वास है, ये प्रोजेक्ट्स ऊर्जा के मामले में भारत की आत्मनिर्भरता के प्रतीक बनेंगे।

साथियों,

अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत, बड़े सोलर प्लांट्स लगाने के साथ ही ज्यादा से ज्यादा घरों में सोलर पैनल लगाने पर भी जोर दे रहा है। लोग आसानी से roof-top solar project लगा पाएं, इसके लिए आज एक नेशनल पोर्टल भी शुरू किया गया है। ये घर पर ही बिजली पैदा करने और बिजली उत्पादन से कमाई, दोनों तरह से मदद करेगा।

सरकार का जोर बिजली का उत्पादन बढ़ाने के साथ ही, बिजली की बचत करने पर भी है। बिजली बचाना यानि भविष्य सजाना, याद रखिए बिजली बचाना मतलब, बिजली बचाना भविष्य सजाना। पीएम कुसुम योजना इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। हम किसानों को सोलर पंप की सुविधा दे रहे हैं, खेतों के किनारे सोलर पैनल लगाने में मदद कर रहे हैं। और इससे अन्नदाता, ऊर्जादाता भी बन रहा है, किसान के खर्च में भी कमी आई है और उसे कमाई का एक अतिरिक्त साधन भी मिला है। देश के सामान्य मानवी का बिजली का बिल कम करने में उजाला योजना ने भी बड़ी भूमिका निभाई है। घरों में LED बल्ब की वजह से हर साल गरीब और मध्यम वर्ग के बिजली बिल में 50 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा बच रहे हैं। हमारे परिवारों में 50 हजार करोड़ रुपये बचना, से अपने-आप में बहुत बड़ी मदद है।

साथियों,

इस कार्यक्रम में अनेक राज्यों के सम्मानित माननीय मुख्यमंत्री और अन्य प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं। इस अवसर एक बहुत ही गंभीर बात और अपनी बड़ी चिंता भी मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। और ये चिंता इतनी बड़ी है कि एक बार हिन्दुस्तान के एक प्रधानमंत्री को 15 अगस्त को लालकिले के भाषण में इस चिंता को व्यक्त करना पड़ा था। समय के साथ हमारी राजनीति में एक गंभीर विकार आता गया है। राजनीति में जनता को सच बताने का साहस होना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ राज्यों में इससे बचने की कोशिश होती है। ये रणनीति तात्कालिक रूप से अच्छी राजनीति लग सकती है। लेकिन ये आज के सच को, आज की चुनौतियों को, कल के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी भावी पीढ़ियों के लिए टालने वाली योजना है, उनका भविष्य तबाह करने वाली बातें हैं। समस्या का समाधान आज ढूंढने के बजाय, उनको ये सोचकर टाल देना कि कोई और इसको समझेगा, कोई और सुलझाएगा, आने वाला जो करेगा, करेगा, मुझे क्या मैं तो पांच साल-दस साल में चला जाऊंगा, ये सोच देश की भलाई के लिए उचित नहीं है। इसी सोच की वजह से देश के कई राज्यों में आज पावर सेक्टर बड़े संकट में है। और जब किसी राज्यका पावर सेक्टर कमजोर होता है, तो इसका प्रभाव पूरे देश के पावर सेक्टर पर भी पड़ता है और उस राज्य के भविष्य को अंधकार की ओर ढकेल देता है।

आप भी जानते हैं कि हमारे Distribution Sector के Losses डबल डिजिट में हैं। जबकि दुनिया के विकसित देशों में ये सिंगल डिजिट में, बहुत नगण्य हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे यहां बिजली की बर्बादी बहुत है और इसलिए बिजली की डिमांड पूरी करने के लिए हमें ज़रूरत से कहीं अधिक बिजली पैदा करनी पड़ती है।

अब सवाल ये है कि डिस्ट्रिब्यूशन और ट्रांसमिशन के दौरान जो नुकसान होता है उसे कम करने के लिए राज्यों में ज़रूरी निवेश क्यों नहीं होता? इसका उत्तर ये है कि अधिकतर बिजली कंपनियों के पास फंड की भारी कमी रहती है। सरकारी कंपनियों का भी ये हाल हो जाता है। इस स्थिति में कई-कई साल पुरानी ट्रांसमिशन लाइनों से काम चलाया जाता है, नुकसान बढ़ता जाता है और जनता को महंगी बिजली मिलती है। आंकड़े बताते हैं कि बिजली कंपनियां बिजली तो पर्याप्त पैदा कर रही हैं लेकिन फिर भी उनके पास ज़रूरी फंड नहीं रहता। और ज्यादातर ये कंपनियां सरकारों की हैं। इस कड़वे सच से आप सभी परिचित हैं। शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि distribution companies का पैसा उनको समय पर मिला हो। उनके राज्य सरकारों पर भारी-भरकम dues रहते हैं, बकाया रहते हैं। देश को ये जानकर हैरानी होगी कि अलग-अलग राज्यों का 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बिल बकाया पड़ा है। ये पैसा उन्हें पावर जेनरेशन कंपनियों को देना है, उनसे बिजली लेनी है, लेकिन पैसे नहीं दे रहे हैं। पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनियों का अनेक सरकारी विभागों पर, स्थानीय निकायों पर भी 60 हजार करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है और चुनौती इतनी ही नहीं है। अलग-अलग राज्यों में बिजली पर सब्सिडी का जो कमिटमेंट किया गया है, वो पैसा भी इन कंपनियों को समय पर और पूरा नहीं मिल पाता। ये बकाया भी, ये बड़े-बड़े वादे करके जो किया गया है ना वो भी बकाया करीब-करीब 75 हजार करोड़ रुपए से अधिक का है। यानि बिजली बनाने से लेकर घर-घर पहुंचाने तक का ज़िम्मा जिनका है, उनका लगभग ढाई लाख करोड़ रुपए फंसा हुआ है। ऐसी स्थिति में इंफ्रास्ट्रक्चर पर, भविष्य की ज़रूरतों पर निवेश हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? क्या हम देश को, देश की आने वाली पीढ़ी को अंधेरे में जीने के लिए मजबूर कर रहे हैं क्या?

साथियों,

ये जो पैसा है, सरकार की ही कंपनियां हैं, कुछ प्राइवेट कंपनियां हैं, उनकी लागत का पैसा है, अगर वो भी नहीं मिलेगा तो फिर कंपनियां न विकास करेंगी, न बिजली के नए उत्पादन होंगे, न ज़रूरतें पूरी होंगी। इसलिए हमें स्थिति की गंभीरता को समझना होगा और बिजली का कारखाना लगाना है तो पांच-छह साल के बाद बिजली आती है। कारखाना लगाने में 5-6 साल चले जाते हैं। इसीलिए मैं सभी देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं, देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रार्थना करता हूं, हमारा देश अंधकार में न जाए, इसके लिए जागरूक होने की ज़रूरत है। और इसलिए मैं कहता हूं ये राजनीति का नहीं राष्ट्रनीति और राष्ट्रनिर्माण का सवाल है, बिजली से जुड़े पूरे सिस्टम की सुरक्षा का सवाल है। जिन राज्यों के dues Pending हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि वे जितना जल्दी संभव हो सके, इन चीजों को क्लीयर करें। साथ ही उन कारणों पर भी ईमानदारी से विचार करें कि जब देशवासी ईमानदारी से अपना बिजली का बिल चुकाते हैं, तब भी कुछ राज्यों का बार-बार बकाया क्यों रहता है? देश के सभी राज्यों द्वारा इस चुनौती का उचित समाधान तलाशना, आज समय की मांग है।

साथियों,

देश के तेज विकास के लिए बहुत ज़रूरी है कि पावर और एनर्जी सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा मजबूत रहे, हमेशा आधुनिक होता रहे। हम उस स्थिति की कल्पना भी कर सकते हैं कि अगर बीते आठ वर्षों में सबके प्रयास से, इस सेक्टर को नहीं सुधारा गया होता, तो आज ही कितनी मुसीबतें आ करके खड़ी हो गई होतीं। बार-बार ब्लैक आउट होते, शहर हो या गांव कुछ घंटे ही बिजली आती, खेत में सिंचाई के लिए किसान तरस जाते, कारखाने थम जाते। आज देश का नागरिक सुविधाएं चाहता है,

मोबाइल फोन की चार्जिंग जैसी चीजें उसके लिए रोटी-कपड़ा और मकान जैसी जरूरत बन गई है। बिजली की स्थिति पहले जैसी होती, तो ये कुछ भी नहीं हो पाता। इसलिए बिजली सेक्टर की मजबूती हर किसी का संकल्प होना चाहिए, हर किसी का दायित्व होना चाहिए, हर किसी को इस कर्तव्य को निभाना चाहिए। हमें याद रखना है, हम अपने-अपने दायित्वों पर खरे उतरेंगे, तभी अमृतकाल के हमारे संकल्प सिद्ध होंगे।

आप लोग भलीभांति, गांव के लोगों से अगर मैं बात करूंगा तो मैं कहूंगा कि घर में सबको घी हो, तेल हो, आटा हो, अनाज हो, मसाले हों, सब्जी हो, सब हो, लेकिन चूल्हा जलने की व्यवस्था न हो तो पूरा घर भूखा रहेगा कि नहीं रहेगा। ऊर्जा के बिना गाड़ी चलेगी क्या? नहीं चलेगी। जैसे घर में अगर चूल्हा नहीं जलता है, भूखे रहते हैं; देश में भी अगर बिजली की ऊर्जा नहीं आई तो सब कुछ थम जाएगा।

और इसलिए मैं आज देशवासियों के सामने बहुत गंभीरतापूर्वक और सभी राज्य सरकारों को करबद्ध प्रार्थना करते हुए मैं प्रार्थना करता हूं कि आइए हम राजनीति के रास्ते से हट करके राष्ट्रनीति के रास्ते पर चल पड़ें। हम मिल करके देश को भविष्य में कभी भी अंधेरे में न जाना पड़े, इसके लिए आज से ही काम करेंगे। क्योंकि बरसों लग जाते हैं इस काम को करने में।

साथियों,

मैं ऊर्जा परिवार के सभी साथियों को बधाई देता हूं इतने बड़े भव्य आयोजन के लिए। देश के कोने-कोने में बिजली को लेकर इतनी बड़ी जागरूकता बनाने के लिए। एक बार फिर नए प्रोजेक्ट्स की भी मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूं, पावर सेक्टर से जुड़े सभी स्टैकहोल्डर्स को शुभकामनाएं देता हूं। मेरी तरफ से आप सबको उज्ज्वल भविष्य की अनेक-अनेक शुभकामनाएं।

बहुत-बहुत धन्यवाद !

DS/TS/NS

(रिलीज आईडी: 1846490) आगंतुक पटल : 415

इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English , Urdu , Marathi , Manipuri , Bengali , Assamese , Punjabi , Gujarati , Odia , Tamil , Telugu , Kannada , Malayalam

प्रधानमंत्री कार्यालय



पानीपत में 2जी इथेनॉल संयंत्र के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री के संबोधन का मूल पाठ

प्रविष्टि तिथि: 10 AUG 2022 7:31PM by PIB Delhi

नमस्कार जी,

हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, केंद्रीय मंत्री परिषद के मेरे सहयोगी नरेंद्र सिंह तोमर जी, हरदीप सिंह पुरी जी, रामेश्वर तेली जी, सांसदगण, विधायकगण, पानीपत में बड़ी संख्या में उपस्थित मेरे प्यारे किसान भाई और बहन, इस कार्यक्रम से जुड़े अन्य सभी महानुभाव, देवियों और सज्जनों, आप सभी को विश्व बायोफ्यूल दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएं !

आज का कार्यक्रम पानीपत, हरियाणा समेत पूरे देश के किसानों के लिए बहुत अहम है। ये जो पानीपत में आधुनिक इथेनॉल का प्लांट लगा है, जैविक ईंधन प्लांट बना है, वो तो एक शुरुआत मात्र है। इस प्लांट की वजह से दिल्ली-एनसीआर और पूरे हरियाणा में प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी। मैं हरियाणा के लोगों को विशेष रूप से किसान बहनों-भाइयों को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। वैसे आज हरियाणा डबल बधाई का हकदार भी है। कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा के बेटे-बेटियों ने बहुत शानदार प्रदर्शन करके देश का माथा ऊंचा किया है, देश को बहुत सारे मेडल दिलाए हैं। खेल के मैदान में जो ऊर्जा हरियाणा के खिलाड़ी दिखाते हैं, वैसे ही अब हरियाणा के खेत भी, ऊर्जा पैदा करके दिखाएंगे।

साथियों,

प्रकृति की पूजा करने वाले हमारे देश में बायोफ्यूल या जैविक ईंधन, प्रकृति की रक्षा का ही एक पर्याय है। हमारे किसान भाई-बहन तो इसे और अच्छी तरह समझते हैं। हमारे लिए जैव ईंधन यानि हरियाली लाने वाला ईंधन, पर्यावरण बचाने वाला ईंधन। आप किसान भाई-बहन तो सदियों से इतने जागरूक हैं कि बीज बोने से लेकर फसल उगाने और फिर उसे बाजार में पहुंचाने तक किसी भी चीज को बर्बाद नहीं होने देते। किसान अपने खेत से उगने वाली हर चीज, उसका बखूबी इस्तेमाल करना जानते हैं। जिस खेत में लोगों के लिए अन्न उगता है, उसी से पशुओं के लिए चारा भी आता है। फसल कटाई के बाद खेत में जो पराली बच जाती है, उसका भी हमारे अधिकतर किसान सही उपयोग करना जानते हैं। पराली का इस्तेमाल पशुओं के चारे के लिए होता है, बहुत से गांवों में, मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए भी पराली उपयोग में लाई जाती है। लेकिन ये भी सच है कि हरियाणा जैसे क्षेत्रों में जहां धान और गेहूं की पैदावार ज्यादा होती है, वहां पराली का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाता था। अब यहां के किसानों को पराली के उपयोग का एक और साधन मिल रहा है। और ये साधन है - आधुनिक इथेनॉल प्लांट, जैविक ईंधन प्लांट। पानीपत के जैविक ईंधन प्लांट से पराली का बिना जलाए भी निपटारा हो जाएगा। और इसके एक नहीं, दो नहीं बल्कि कई सारे फायदे एक साथ होने वाले हैं। पहला फायदा तो ये होगा कि पराली जलाने से धरती मां को जो पीड़ा होती थी, जो आग में धरती मां झुलसती थी, उस पीड़ा से धरती मां को मुक्ति मिलेगी। धरती मां को भी अच्छा लगेगा कि पराली का अब सही जगह इस्तेमाल हो रहा है। दूसरा फायदा ये होगा कि पराली काटने से लेकर उसके निस्तारण के लिए जो नई व्यवस्था बन रही है, नई मशीनें आ रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए नई सुविधा बन रही है, जो ये नए जैविक ईंधन प्लांट लग रहे हैं, इन सबसे गांवों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। ग्रीन जॉब का क्षेत्र मजबूत होगा। तीसरा फायदा होगा कि जो पराली किसानों के लिए बोझ थी, परेशानी का कारण थी, वही उनके लिए, अतिरिक्त आय का माध्यम बनेगी। चौथा फायदा ये होगा कि प्रदूषण कम होगा, पर्यावरण की रक्षा में किसानों का योगदान और बढ़ेगा। और पांचवा लाभ ये होगा कि देश को एक वैकल्पिक ईंधन भी मिलेगा। यानि पहले जो पराली नुकसान का कारण बनती थी, उसी से ये पांच अमृत निकलेंगे। मुझे खुशी है कि देश के अलग-अलग हिस्सों में ऐसे कई जैविक ईंधन प्लांट्स लगाने का काम किया जा रहा है।

साथियों,

जिन लोगों में राजनीतिक स्वार्थ के लिए शॉर्ट-कट अपनाकर, समस्याओं को टाल देने की प्रवृत्ति होती है, वो कभी समस्याओं का स्थाई समाधान नहीं कर सकते। शॉर्ट-कट अपनाने वालों को कुछ समय के लिए वाहवाही भले मिल जाए, राजनीतिक फायदा भले हो जाए, लेकिन समस्या कम नहीं होती। इसलिए ही मैं कहता हूँ कि शॉर्ट-कट अपनाने से शॉर्ट-सर्किट अवश्य होता है। शॉर्ट-कट पर चलने के बजाय हमारी सरकार समस्याओं के स्थाई समाधान में जुटी है। पराली की दिक्कतों के बारे में भी बरसों से कितना कुछ कहा गया। लेकिन शॉर्टकट वाले इसका समाधान नहीं दे पाए। हम किसानों की पराली से जुड़ी समस्याओं को समझते हैं, इसलिए उन्हें इससे छुटकारा पाने के आसान विकल्प भी दे रहे हैं।

हमने जो किसान उत्पाद संघ हैं, FPO's हैं, उन्हें पराली के निस्तारण के लिए आर्थिक मदद दी। इससे जुड़ी आधुनिक मशीनों की खरीद के लिए 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी भी दी। अब पानीपत में लगा ये जैविक ईंधन प्लांट भी पराली की समस्या के स्थाई समाधान में मदद करने वाला है। इस आधुनिक प्लांट में धान और गेहूँ के भूसे के साथ ही मक्के का बचा हुआ हिस्सा, गन्ने की खोई, सड़ा-गला अनाज, इन सभी का इस्तेमाल इथेनॉल बनाने में किया जाएगा। यानि किसानों की बहुत बड़ी चिंता समाप्त होगी। हमारे अन्नदाता जो मजबूरी में पराली जलाते थे, जिन्हें इस वजह से बदनाम कर दिया गया था, उन्हें भी अब गर्व होगा कि वो इथेनॉल या जैविक ईंधन के उत्पादन में भी मदद कर रहे हैं, राष्ट्र निर्माण में मदद कर रहे हैं। गाय-भैंसों से जो गोबर होता है, खेतों से जो कचरा निकलता है, उसके निपटारे के लिए सरकार ने और एक योजना चलाई है, गोबरधन योजना भी शुरू की है। गोबरधन योजना भी किसानों की आय बढ़ाने का एक और माध्यम बन रही है।

साथियों,

आज़ादी के इतने दशकों तक हम फर्टिलाइज़र हो, केमिकल हो, खाने का तेल हो, कच्चा तेल हो, गैस हो, इनके लिए विदेशों पर बहुत अधिक निर्भर रहे हैं। इसलिए जैसे ही वैश्विक परिस्थितियों की वजह से सप्लाई चेन में अवरोध आता है, भारत भी दिक्कतों से बच नहीं सकता। बीते 8 वर्षों से देश इन चुनौतियों के स्थाई समाधान पर भी काम कर रहा है। देश में नए फर्टिलाइज़र प्लांट लग रहे हैं, नैनो फर्टिलाइज़र का उत्पादन हो रहा है, खाद्य तेल के लिए नए-नए मिशन भी शुरू हुए हैं। आने वाले समय में ये सभी देश को समस्याओं के स्थाई समाधान की तरफ ले जाएंगे।

साथियों,

आज़ादी के अमृतकाल में देश आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। हमारे गांव और हमारे किसान आत्मनिर्भरता के सबसे बड़े उदाहरण हैं। किसान अपनी जरूरत की चीजें काफी हद तक अपने गांव में ही जुटा लेते हैं। गांव की सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था ऐसी होती है कि जब एक-दूसरे की जरूरतों को पूरा भी करने के लिए सब साथ आ जाते हैं। यही वजह है कि गांव के लोगों में बचत की प्रवृत्ति भी बहुत मजबूत होती है। उनकी ये प्रवृत्ति देश के पैसे भी बचा रही है। पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से बीते 7-8 साल में देश के करीब-करीब 50 हजार करोड़ बाहर विदेश जाने से बचे हैं। और करीब-करीब इतने ही हजार करोड़ रुपए इथेनॉल ब्लेडिंग की वजह से हमारे देश के किसानों के पास गए हैं। यानि जो पैसे विदेश जाते थे, वो एक तरह से हमारे किसानों को मिले हैं।

साथियों,

21वीं सदी के नए भारत में एक और बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। आज देश बड़े संकल्प ले रहा है और उन्हें सिद्ध भी करके दिखा रहा है। कुछ साल पहले देश ने तय किया था कि पेट्रोल में 10 प्रतिशत तक इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य पूरा करेंगे। हमारे किसान भाई-बहनों की मदद से, देश ने ये लक्ष्य समय से पहले ही हासिल कर लिया। आठ साल पहले हमारे देश में इथेनॉल का उत्पादन सिर्फ 40 करोड़ लीटर के आसपास होता था। आज करीब-करीब 400 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन हो रहा है। इतनी बड़ी मात्रा में इथेनॉल बनाने के लिए कच्चा माल हमारे किसानों के खेतों से ही तो आता है। खासकर गन्ना किसानों को इससे बहुत बड़ा लाभ हुआ है।

देश कैसे बड़े लक्ष्य हासिल कर रहा है, इसका मैं अपने किसान भाई-बहनों को एक और उदाहरण देता हूँ। 2014 तक देश में सिर्फ 14 करोड़ के आसपास एलपीजी गैस कनेक्शन थे। देश की आधी आबादी को, माताओं-बहनों को रसोई के धुएं में छोड़ दिया गया था। बहनों-बेटियों के खराब स्वास्थ्य और असुविधा से जो नुकसान होता है, उसकी पहले परवाह ही नहीं की गई। मुझे खुशी है कि आज उज्जवला योजना से ही 9 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन गरीब बहनों को दिए जा चुके हैं। अब हम देश में करीब-करीब शत-प्रतिशत एलपीजी कवरेज तक पहुंच चुके हैं। 14 करोड़ से बढ़कर आज देश में करीब 31 करोड़ गैस कनेक्शन हैं। इससे हमारे गरीब परिवार, मध्यम वर्ग के लोगों को बहुत ज्यादा सुविधा हुई है।

साथियों,

देश में CNG नेटवर्क बढ़ाने और पाइप से सस्ती गैस घर-घर पहुंचाने के लिए भी तेज़ी से काम चल रहा है। हमारे देश में 90 के दशक में CNG स्टेशन लगाने शुरू हुए थे। 8 साल पहले तक देश में CNG के 800 से भी कम स्टेशन थे। घरों में पाइप से आने वाली गैस के कनेक्शन भी कुछ लाख ही थे। आज देशभर में साढ़े 4 हजार से अधिक CNG स्टेशन हैं और पाइप से गैस के कनेक्शन का आंकड़ा 1 करोड़ को छू रहा है। आज जब हम आजादी के 75 वर्ष पूरे कर रहे हैं, तो देश इस लक्ष्य पर भी काम कर रहा है कि अगले कुछ वर्षों में देश के 75 प्रतिशत से ज्यादा घरों में पाइप से गैस पहुंचने लगे।

साथियों,

आज जो सैकड़ों किलोमीटर लंबी गैस पाइप लाइनें हम बिछा रहे हैं, जो आधुनिक प्लांट, जो फैक्ट्रियां, हम लगा रहे हैं, इनका सबसे अधिक लाभ हमारी युवा पीढ़ी को होगा। देश में Green Jobs के निरंतर नए अवसर बनेंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। आज की समस्याएं हमारी भावी पीढ़ियों को कष्ट नहीं देंगीं। यही सही विकास है, यही विकास की सच्ची प्रतिबद्धता है।

साथियों,

अगर राजनीति में ही स्वार्थ होगा तो कोई भी आकर पेट्रोल-डीजल भी मुफ्त देने की घोषणा कर सकता है। ऐसे कदम हमारे बच्चों से उनका हक छीनेंगे, देश को आत्मनिर्भर बनने से रोकेंगे। ऐसी स्वार्थ भरी नीतियों से देश के ईमानदार टैक्स पेयर का बोझ भी बढ़ता ही जाएगा। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ऐसी घोषणाएं करने वाले कभी नई टेक्नॉलॉजी पर निवेश नहीं करेंगे। वो किसान से झूठे वायदे करेंगे, लेकिन किसानों की आय बढ़ाने के लिए इथेनॉल जैसे प्लांट नहीं लगाएंगे। वो बढ़ते प्रदूषण पर हवा-हवाई बातें करते रहेंगे, लेकिन इसको रोकने के लिए जो कुछ करना होगा, उससे दूर भागेंगे।

मेरे प्यारे भाइयो, बहनों,

ये नीति नहीं, अनीति है। ये राष्ट्रहित नहीं, ये राष्ट्र अहित है। ये राष्ट्र निर्माण नहीं, राष्ट्र को पीछे धकेलने की कोशिश है। देश के सामने जो चुनौतियां हैं, उनसे निपटने के लिए साफ नीयत चाहिए, निष्ठा चाहिए, नीति चाहिए। इसके लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करनी पड़ती है और सरकार को बहुत सारी राशि निवेश करनी पड़ती है। जब सरकारों के पैसा होगा ही नहीं, उसके पास धन ही नहीं होगा तो इथेनॉल प्लांट, बायोगैस प्लांट, बड़े-बड़े सोलर प्लांट, हाइड्रोजन गैस के प्लांट जो आज लग रहे हैं, वो भी बंद हो जाएंगे। हमें ये याद रखना है कि हम भले ही रहें या न रहें, लेकिन ये राष्ट्र तो हमेशा रहेगा, सदियों से रहता आया है, सदियों तक रहने वाला है। इसमें रहने वाली संतानें हमेशा रहेंगी। हमें हमारी भावी संतानों के भविष्य को बर्बाद करने का हक नहीं है।

साथियो,

आजादी के लिए अपना जीवन बलिदान करने वालों ने भी इसी शाश्वत भावना से काम किया है। अगर वो भी तब अपना सोचते, अपना स्वार्थ देखते तो उनके जीवन में भी कोई कष्ट नहीं आता। वो कठिनाइयों से, गोलियों से, फांसी के फंदे से, यातनाओं से बच जाते, लेकिन उनकी संतानें, यानि हम भारत के लोग, आज आजादी का अमृत महोत्सव नहीं मना पाते। अगस्त का ये महीना क्रांति का महीना है। इसलिए एक देश के रूप में हमें ये संकल्प लेना है कि ऐसी हर प्रवृत्ति को बढ़ने नहीं देंगे। ये देश का सामूहिक दायित्व है।

साथियों,

आजादी के इस अमृत महोत्सव में, आज जब देश तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है, तब कुछ ऐसा भी हुआ है, जिसकी तरफ मैं देश का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों को अपमानित करने का, इस पवित्र अवसर को अपवित्र करने का प्रयास किया गया है। ऐसे लोगों की मानसिकता देश को भी समझना जरूरी है। हम जानते हैं कभी-कभी कोई मरीज अपनी लंबी बीमारी के इलाज से थक जाता है, निराश हो जाता है, अच्छे-अच्छे डॉक्टरों से सलाह लेने के बावजूद जब उसे लाभ नहीं होता, तो वो कितना ही पढ़ा-लिखा क्यों न हो, अंधविश्वास की तरफ बढ़ने लग जाता है। वो झाड़-फूंक कराने लगता है, टोने-टोटके पर, काले जादू पर विश्वास करने लगता है। ऐसे ही हमारे देश में भी कुछ लोग हैं जो नकारात्मकता के भंवर में फंसे हुए हैं, निराशा में डूबे हुए हैं। सरकार के खिलाफ झूठ पर झूठ बोलने के बाद भी जनता जनार्दन ऐसे लोगों पर भरोसा करने को तैयार नहीं हैं। ऐसी हताशा में ये लोग भी अब काले जादू की तरफ मुड़ते नजर आ रहे हैं।

अभी हमने 5 अगस्त को देखा है कि कैसे काले जादू को फैलाने का भरपूर प्रयास किया गया। ये लोग सोचते हैं कि काले कपड़े पहनकर, उनकी निराशा-हताशा का काल समाप्त हो जाएगा। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो कितनी ही झाड़ू-फूंक कर लें, कितना ही काला जादू कर लें, अंधविश्वास कर लें, जनता का विश्वास अब उन पर दोबारा कभी नहीं बन पाएगा। और मैं ये भी कहूंगा कि इस काले जादू के फेर में, आजादी के अमृत महोत्सव का अपमान ना करें, तिरंगे का अपमान ना करें।

साथियों,

कुछ राजनीतिक दलों की स्वार्थ नीति से अलग, हमारी सरकार सबका साथ-सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर काम करती रहेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि विकास के लिए सकारात्मक विश्वास की ऊर्जा इसी तरह पैदा होती रहेगी। एक बार फिर हरियाणा के कोटि-कोटि साथियों को, किसान और पशुपालक बहन-भाइयों को बधाई। कल रक्षा बंधन का पवित्र त्योहार भी है। भाई-बहन के स्नेह के प्रतीक इस पर्व पर, हर भाई अपना कर्तव्य निभाने का संकल्प दोहराता है। कल एक नागरिक के तौर पर भी हमें देश के प्रति अपने कर्तव्य निभाने का संकल्प दोहराना है। इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद !

DS/TS/NS

(रिलीज़ आईडी: 1850618) आगंतुक पटल : 637

इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English , Urdu , Marathi , Assamese , Manipuri , Bengali , Punjabi , Gujarati , Odia , Tamil , Telugu , Malayalam